भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास - पीछे देखते हुए आगे देखना*

दुव्वुरी सुब्बाराव

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से, आदरणीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास के खंड IV के इस विमोचन समारोह में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी है।

2. भरिबैंक का इतिहास के खंड IV में 1981 से 1997 की अवधि शामिल है। इसमें वह अवधि शामिल है जब प्रधान मंत्री 1982-1985 तक की अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे और इसके बाद वे 1991 से 1996 तक वित्तमंत्री रहे। इसलिए इतिहास के विमोचन का आज का यह समारोह अपने आप में ऐतिहासिक है।

1935 से भारिबैंक

3. 1935 में स्थापित, भारतीय रिज़र्व बैंक विकासशील देशों में पुराने केंद्रीय बैंकों में से एक है। रिज़र्व बैंक का इतिहास कई अर्थों में भारत के आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। लगभग आठ दशकों में बैंक की यात्रा ने देश एवं विदेश दोनों में अनेक ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव देखे हैं; जैसे - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 1930 के दशक की महा मंदी के बाद का परिणाम; द्वितीय विश्व युद्ध और युद्ध के फलस्वरूप वित्तपोषण की चुनौतियां; 1944 में ब्रिटेन वुड्स प्रणाली की स्थापना; स्वर्ण मान की समस्या सुलझाना तथा 1970 के दशक में तेल की कीमतों के आघात; 1990 के मध्य का एशियाई संकट; तथा हाल ही में वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल और निरंतर हो रहे यूरोजोन का सार्वभौम ऋण संकट।

4. देश के मोर्च पर भी अनेक ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव हुए थे - पंचवार्षिक योजनाओं की शुरुआत से शुरू करके आर्थिक विकास में इतिहास की एक सबसे महत्त्वकांक्षी एवं विशालकाय प्रयोगों से उत्पन्न चुनौतियां; 1960 के दशक में दो युद्ध के बाद के प्रभाव; 1966 में रुपये का अवमूल्यन; 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण; 1990 के दशक के शुरू में भुगतान संतुलन का संकट और उस उल्लेखनीय आर्थिक सुधारों को जारी रखना जिसने भारत को नये आर्थिक युग में ला दिया। रिज़र्व बैंक ने इन उतार-चढ़ावों को आकार देने में या, जैसी भी स्थिति हो, उनके प्रति कार्रवाई करने में जो भूमिका अदा की उस पर उसे गर्व है और ऐसा वह संवेदनशीलता तथा ईमानदारी से सदा करता है।

भारिबैंक का इतिहास - पिछले खंड

5. रिज़र्व बैंक में हम सभी के लिए यह गर्व एवं संतोष की बात है कि वह केंद्रीय बैंकों में से उन कुछ गिने-चुने बैंकों में से एक है जिसने अपनी संस्था का इतिहास लिपिबद्ध किया है। अब तक हमने इतिहास के तीन खंड प्रकाशित किए हैं जिसमें बैंक की शुरुआत से 1981 तक की अवधि शामिल है। खंड I में 1935 से 1951 तक की अवधि का लेखा-जोखा है। भारत में केंद्रीय बैंक स्थापित किये जाने के प्रारंभिक प्रयासों को विशेषकर इसमें स्थान दिया गया है। जान मेनार्ड किन्स ने 1913 में इस दिशा में एक ठोस प्रस्ताव दिया था कि केंद्रीय बैंक के कुछ कार्यों को हाथ में लेने के लिए तीन प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय करके भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए। खंड II में 1951 से 1967 तक के विकास-आयोजना की प्रक्रिया में रिज़र्व बैंक की भूमिका का उल्लेख है। इतिहास के तीसरे खंड में 1967 से 1981 तक की अवधि शामिल की गई है जिसमें भारत के दूर-दराज के इलाकों तक बैंकिंग को पहुंचाने में रिज़र्व बैंक के प्रयासों का वर्णन है।

भारिबैंक का इतिहास - खंड IV

6. इस खंड IV में 1981 से 1997 की अवधि शामिल की गई है। इस अवधि में 6 गवर्नरों का नेतृत्व बैंक को मिला। इन अवधि के अंतिम चरण में आइ.जी. पटेल इसके गवर्नर थे।

1.	डा. आइ.जी. पटेल	:	01.12.1977 से 15.09.1982
2.	डॉ. मनमोहन सिंह	:	16.09.1982 से 14.01.1985
3.	श्री अमिताभ घोष	:	15.01.1985 से 04.02.1985
4.	श्री आर.एन. मल्होत्रा	:	04.02.1985 से 22.12.1990
5.	श्री एस.वेंकिट रमणन	:	22.04.1990 से 21.12.1992
6.	डा. सी. रंगराजन	:	22.12.1992 से 21.11.1997

7. प्रधान मंत्री के अलावा, यहां उपस्थित उस अवधि के दो पूर्व अन्य गवर्नरों - श्री अमिताभ घोष तथा डा. रंगराजन - का मैं स्वागत करता हूँ। श्री वेंकट रमणन आज यहां उपस्थित

*17 अगस्त 2013 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय रिर्जव बैंक का इतिहास के खंड IV के विमोचन अवसर पर डा. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, का स्वागत वक्तव्य।

नहीं है, किंतु उन्होंने इस समारोह के लिए अपनी शुभ कामना भेजी है। चूंकि यह ऐतिहासिक क्षण है, अतः इस अवसर पर दिवंगत डा. आइ.जी. पटेल तथा श्री आर.एन. मल्होत्रा की भी हमें याद आती है। इन दोनों ने रिज़र्व बैंक की सेवा बड़ी गरिमा एवं उत्कृष्ट ढंग से की।

8. भारिबैंक के इतिहास के इस चौथे खंड में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सर्वाधिक चुनौती पूर्ण समय था। इस इतिहास के दौरे में हमें कठिन समय से गुजरना पड़ा क्योंकि सरकार और रिज़र्व बैंक दोनों को विदेशी भुगतानों की स्थिति के संबंध में अभूत पूर्व दबाव का सामना करना पड़ा। भुगतान-संतुलन संकट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सरकार को आर्थिक सुधारों में कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने पड़े जिससे देश के आर्थिक प्रबंधन में बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना पड़ा। इस उत्तेजना-भरी प्रक्रिया में विचारों को पैदा करने में प्रस्तावों की प्रक्रिया शुरू करने में तथा सुधारों के लिए पहल को लागू करने में रिज़र्व बैंक की भागीदारी थी। इस खंड के अध्याय 10 एवं 12 में हमारे आर्थिक इतिहास के इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण चरण का स्पष्ट लेखाजोखा दिया गया है।

क्या इतिहास अपने को दोहराता है?

9. क्या इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है? यह एक घिसापिटा सवाल है, फिर भी इसमें एक शिक्षा प्रद बात है। बड़े परिश्रमपूर्वक अनुसंधान के बाद लिखी गई अपनी पुस्तक 'दिस टाइम इज डिफरेन्टः एट सुन्चुरिज़ ऑफ फाइनानशियल फॉलि' में केनीथ रोगॉफ एण्ड कारमेन रेनहार्ट ने यह तर्क दिया है कि हर समय कोई संकट पैदा होता है, विशेषज्ञों से पूछा गया कि क्यों वे इसे देख नहीं पाए। प्रत्येक बार, विशेषज्ञों ने उत्तर दिया कि विगत अनुभव इसका मार्गदर्शक नहीं है क्योंकि अद्यतन संकट नई परिस्थितियों का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, उनका मानक उत्तर यह रहा - 'यह समय अलग है।' फिर भी, 'यह समय अलग है' का तर्क कुछ जँचता नहीं। रेनहार्ट तथा रोगॉफ ने असरदार साक्ष्य देते हुए यह दिखाया है कि विगत आठ सौ वर्षों से, सभी प्रकार के वित्तीय संकट के वही मूलभूत कारण खोजे जा सकते हैं, मानो हमने एक संकट से दूसरे संकट के बारे में कुछ सीखा नहीं।

10. अतः, अनुमान यह है कि कम-से-कम अर्थशास्त्र एवं वित्त के मामलों में इतिहास अपने को दोहराता है। इसका कारण यह नहीं कि यह इतिहास का एक स्वाभाविक गुण है, बल्कि यह कि हम इतिहास से सीखते नहीं और ऐसा बार-बार होने देते हैं। मेरा विश्वास है कि यह अनुमान रेनहार्ट-रोगॉफ के अनुसंधान में कंप्यूटर प्रोग्राम (स्प्रेडशीट) में भूल होते हुए भी सही लगता है।

11. क्या रिज़र्व बैंक के इतिहास ने अपने को दोहराया है? यह न्याय की मांग है। किंतु कुछ मुद्दे भारिबैंक के इतिहास में दोहराए जाते रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा।

भारिबैंक तथा स्वर्ण

12. स्वर्ण का मुद्दा लीजिए। भारिबैंक का इतिहास यह बताता है कि लगभग 35 वर्ष पहले, रिज़र्व बैंक सोने की नीलामी के विषय में एक विवाद में फंस गया। पुनः, 1991 में देश में गरमागरम, भावुक भी, उस समय बहस छिड़ गई जबकि रिज़र्व बैंक को अपना स्वर्ण रिज़र्व गिरवी रखना पड़ा ताकि भुगतान संतुलन के दबाव से वह मुक्त हो जाए। यह अनुमान लगाना दिलचस्प बात होगी कि 2010 में आइएमएफ से रिज़र्व बैंक ने 200 मीटरिक टन सोने की खरीद को इतिहास कैसा मानेगा और अभी हाल ही की अपनी नीतियों में सोना आयात से वह परहेज कर रहा है।

भावी सोच

13. जब चीन के पूर्व प्रधान मंत्री चाऊ इन लाइ से पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति के विषय में उनके क्या विचार हैं। उनका उत्तर था कि इस बारे में कुछ बताना अभी जल्दबाजी होगी। चीनी अनुभव-जन्य ज्ञान को चुनौती देना भीरु व्यक्ति का काम नहीं है। फिर भी; भविष्य को देखने का मैं उत्सुक हूँ कि कैसे वर्तमान चर्चाओं में से कुछ के बारे में इतिहास रिजर्व बैंक का मूल्यांकन करेगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ मुद्दों को परिभाषित करने की मुझे अनुमति दें।

वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन

14. सर्व प्रथम; और संभवतः सबसे महत्त्वपूर्ण चर्चा, नीति के संबंध में वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के बीच संतुलन के बारे में करनी है। यह वह संतुलन है जिससे सरकार तथा रिज़र्व बैंक दोनों ही जूझ रहे हैं। मेरे विचार से; कुछ ज्यादा सरलीकरण ने इस चर्चा को धुंधला बना दिया है। ऐसे ही एक ज्यादा सरलीकरण का यह कहना है कि सरकारें तो वृद्धि चाहती हैं किंतु केंद्रीय बैंक कीमत स्थिरता के पक्ष में हैं। एक दूसरा ज्यादा सरलीकरण इस बात पर जोर देता है कि वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के बीच तनाव है, और नीति-निर्माण में वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के बीच आवश्यक रूप से संतुलन बनाए रखना भी होगा।

15. रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के तीन उद्देश्य हैं - कीमत-स्थिरता, वृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता। दावे के साथ यह कहना कि रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति से अभिभूत है, वृद्धि की चिंताओं के प्रति वह उदास है; इस बारे में मेरा विचार है कि ये दोनों गलत एवं अनुचित हैं। रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति के नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए नहीं कि उसे वृद्धि की चिंता नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे वृद्धि की चिंता है। यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि निरंतर वृद्धि के लिए कम और स्थिर मुद्रास्फीति का वातावरण एक आवश्यक पूर्वशर्त है। इतिहास रिज़र्व बैंक को वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के प्रति उसकी संतुलित प्रतिबद्धता के बारे में कैसे मूल्यांकन करेगी, यह एक दिलचस्प अनुमान है।

मौद्रिक नीति का राजकोषीय वर्चस्व

16. न केवल भारत में, बल्कि विश्व में अनेक देशों में आज एक दूसरी बड़ी चर्चा मौद्रिक नीति के राजकोषीय वर्चस्व के विषय में है। आज यूरोप में बड़े स्तर पर यह मुद्दा उठाया जा रहा है, किंतु यह नया नहीं है; न ही यूरोप में यह अनोखा है।

यहां भारत में, वित्त मंत्री के रूप में डा. मनमोहन सिंह; रिज़र्व बैंक में डा. रंगराजन तथा डा.वाई.वी.रेड्डी और वित्त सचिव के रूप में श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने ढांचागत सुधारों की शुरुआत की जिसने राजकोषीय नीति की विवशता से मुक्त भारत में मौद्रिक नीति की स्वायत्तता को स्थापित करने में सहायता की। विगत पांच वर्षों के अनुभव ने यह दिखाया है कि उस स्वायत्तता के बावजूद मौद्रिक नीति प्रबंधन के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के परिमाण सरकार के राजकोषीय उदाहरण द्वारा सीमित किए जा सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था के रूप में, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों के बीच इस तनाव को हमने कैसे संभाला, इसके विषय में इतिहास का निर्णय क्या होगा?

वैश्विक दुनिया में प्रबंध - नीति

17. भविष्य के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए चुनौतियों के विषय में मुझ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। भविष्य को देखते हुए; रिज़र्व बैंक के लिए बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती आर्थिक एवं विनियामक दोनों प्रकार की नीतियों का वैश्विक दुनिया में प्रबंध करना सीखना होगा। गवर्नर के रूप में डा. जालान ने 1990 के मध्य में एशियाई संकट के असर से भारत को बचाए रखने में असाधारण सक्षमता तथा नेतृत्व का परिचय दिया। डा. रेड्डी ने पार्टी के संहारक होने से पहले ही दिखावटी भय को दूर करने का दृढ़ संकल्प दिखाया।

18. फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट इतना खतरनाक हो गया था कि वास्तव में उसने पूरी दुनिया के हर देश को प्रभावित किया। क्या रिज़र्व बैंक ने वर्तमान संकट को संभालने में डा. जालान की दूरदर्शिता और डा. रेड्डी की समझदारी से सीख ली? नामोदिष्ट गवर्नर राजन, जो अगले महीने के शुरू में मुझ से यह पद संभालेंगे, यहां श्रोताओं में उपस्थित हैं। गवर्नर राजन, आप के सामने चुनौती यह होगी कि कैसे आप अपने विशाल ज्ञान का, विद्वत्ता का, वैश्विक अनुभव का उपयोग रिज़र्व बैंक को एक ज्ञानवान संस्था के रूप में ढालने के लिए करेंगे ताकि यह पता चल सके कि आज की वैश्विक दुनिया में समष्टि आर्थिक नीति का प्रबंध उभरती हुई अर्थव्यवस्था में करने के लिए केंद्रीय बैंक मानक स्थापित करे। मुझे इस बात का पता है कि यह भविष्य का इतिहास है; किंतु फिर भी वह ऐतिहासिक होगा।

अद्यतन विकास की जानकारी रखना

19. 2008 में जब मुझे रिज़र्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब यहां का कार्यभार लेने से पहले मैंने प्रधान मंत्री से भेंट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वे बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मेरे दिमाग में घुस गई : ''सुब्बाराव; आइएएस में अपना दीर्घकालीन अनुभव लेकर रिज़र्व बैंक में आप जा रहे हैं। रिज़र्व बैंक में, असली दुनिया से संपर्क में न रहने का जोखिम है। वहां आप के दिमाग में हमेशा ही ब्याज - दरें, चलनिधि का जाल तथा मौद्रिक नीति के संप्रेषण-जैसे मुद्दे पूरी तरह छाए रहेंगे। यह भूल जाना आसान है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य भूख तथा कुपोषण को कम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, नौकरियां निर्मित करना, सड़कें तथा पुल बनाना और हमारे खेतों एवं फर्मों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना भी है। आप अद्यतन विकास की जानकारी रखें।''

20. रिज़र्व बैंक में अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में; मैंने इस विवेकपूर्ण सलाह का अपनी पूरी योग्यता के साथ पालन किया। मेरा विश्वास है कि आज रिज़र्व बैंक पहले की तुलना में इस बात के लिए ज्यादा सचेत है कि जिन नीतियों को वह बनाता और उनका कार्यान्वयन करता है उनका एक अर्थ है, बशर्ते की असली दुनिया में उनका सकारात्मक असर भी पड़े। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बारे में रिज़र्व बैंक अभी भी अत्यधिक तीव्र शिक्षण वक्र की स्थिति में ही है। कैसे रिज़र्व बैंक इस शिक्षण वक्र को उलट सकेगा? इससे भावी वर्षों में न

केवल रिज़र्व बैंक का इतिहास तय होगा, अपितु, कुछ मामलों में, भारत का इतिहास भी निश्चित होगा।

धन्यवाद

21. मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इतिहास के इस खंड को तैयार करने के मार्गदर्शन का काम एक परामर्शदात्री समिति ने किया था और इसके अध्यक्ष डा. बिमल जालान थे। इस समिति के सदस्य डा. सुबीर गोकर्ण तथा डा.राकेश मोहन थे। ये दोनों ही बैंक के पूर्व उप गवर्नर थे। डा. ए.वासुदेवन, पूर्व कार्यपालक निदेशक, आइआइएम, कोलकाता के डा. अमितव बोस तथा आइजीआइडीआर, मुंबई के प्रो. दिलीप नाचने भी उस समिति के सदस्य थे। कार्यपालक निदेशक दीपक मोहंती के मार्गदर्शन में, रिज़र्व बैंक के इतिहास कक्ष में स्टाफ सदस्यों तथा परामर्शदाताओं ने अनुकरणीय अध्ययन, विवेक एवं प्रतिबद्धता के साथ यह खंड तैयार किया। परामर्शदात्री समिति, स्टाफ तथा परामर्शदाताओं के इस कार्य के लिए मैं हृदय से उनकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने जो काम किया है उससे उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा।

22. अंत में, प्रधान मंत्री महोदय, इतिहास के इस खंड के आज विमोचन के लिए सहमति देने के प्रति आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। रिज़र्व बैंक में हम सभी के लिए इसका बहुत बड़ा अर्थ है।

23. अब मैं डा. जालान से अनुरोध करता हूँ कि इतिहास के इस खंड को लिखने की शुरुआत के लिए उन्होंने जो प्रभूत बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया है उसके विषय में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं।